बाढ़ से हालत खराब, राहत कार्य में तेजी

चंडीगढ़/कुरुक्षेत्र, 1 सितंबर. पंजाब और हरियाणा में बाढ़ और भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. हालात की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने राहत कार्यों को तेज करने के लिए राज्य भर में अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियों के साथ मैदान में उतारा है.

वहीं, प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां दिन-रात प्रभावित लोगों की सहायता में जुटी हैं. पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भाजपा ने राहत और बचाव कार्यों को गति देने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई है. भाजपा ने प्रदेश स्तर के नेताओं को विभिन्न जिलों का प्रभारी नियुक्त किया है, जो स्थानीय स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी करेंगे और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाएंगे. पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार, कपूरथला की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश को सौंपी, जबकि तरनतारन, फाजिल्का, पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर देहात और गुरदासपुर जिलों की जिम्मेदारी अन्य वरिष्ठ नेताओं को दी गई है. भाजपा का कहना है कि यह कदम राहत कार्यों को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है.

सीएम भजनलाल ने मदद करने भगवंत मान से की बात

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय पहल करते हुए प्रदेश के सीमावर्ती पंजाब के फाजिल्का एवं फिरोजपुर जिलों में सतलज, व्यास एवं रावी नदी में जल स्तर बढ़ने से बनी बाढ़ की स्थिति में मदद करने के लिए वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री शर्मा ने श्री मान से फोन पर बात कर पंजाब के जिलों में राहत कार्यों के लिये हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को पंजाब में पड़ौसी जिलों को यथायोग्य मदद करने के निर्देश दिए जिससे किसी भी प्रकार की आपदा में राजस्थान के अधिकारी राहत का काम करेंगे.

हरियाणा में 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया गया है. सिरसा, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र जिलों में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. जालंधर में लगातार बारिश के कारण सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. जिला उपायुक्त डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने हालात का जायजा लिया और राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

पीएम मोदी आज करेंगे बिहार राज्य जीविका सहकारी संघ का शुभारंभ

नई दिल्ली. 1 सितम्बर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ करेंगे और संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित करेंगे.

जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध करना है. जीविका निधि के सभी पंजीकृत संकुल-स्तरीय संघ इसके सदस्य बनेंगे. संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार भी धनराशि देगी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि जीविका निधि के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में कई छोटे उद्यम और उत्पादक कंपनियां स्थापित हुई हैं. राज्य की महिला उद्यमी अब तक विकल्प के अभाव में 18 से 24 प्रतिशत की ऊँची ब्याज दर वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर निर्भर थी. जीविका निधि की व्यवस्था वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली के रूप में की गई है ताकि सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर निर्भरता कम की जा सके.

पटना मेट्रो में नियुक्ति के नाम पर ठगी

पटना, 1 सितंबर. पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी के नाम पर ठगों के कई गिरोह राज्य में सक्रिय हो चुके हैं. पटना मेट्रो में नौकरी के नाम पर ठगों का यह गिरोह लोगों से न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन तरीके से ठगी के नए-नए तरीके अपना रहा है. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि पीएमआरसीएल के नाम पर कुछ फर्जी विज्ञापन विभिन्न माध्यमों जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप लिंक और अवैध वेबसाइट्स के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं. इन फर्जी विज्ञापनों में पटना मेट्रो में युवकों व युवतियों को नौकरी देने का दावा किया जा रहा है.

सालों बाद सड़क मार्ग से साय पहुंचे दंतेवाड़ा

बाढ़ प्रभावित परिवार के लोगों से की सीधी बातचीत

जगदलपुर, 1 सितंबर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक सड़क मार्ग के जरिए पहुंचे. दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में आकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित परिवार के लोगों से बातचीत की है.

मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभाव से मुक्त कर लिए जाने का लक्ष्य केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रखा है. इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के वास्ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसी साल दो बार छत्तीसगढ़ आ चुके हैं. यहां उन्होंने दो बार समीक्षा बैठक की है.

एक बार की समीक्षा बैठक में सभी नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने हिस्सा लिया था. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावितों से मिलकर, राहत कार्यों की जमीनी हकीकतों को खुद से देखा और परखा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह साल 2018 में जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक की दूरी सड़क मार्ग के जरिए ही पूरी की थी.

नक्सल प्रभावित राज्य में एक मुख्यमंत्री का लंबी दूरी तक सड़क मार्ग से आवागमन करना यह बताता है कि राज्य में सुरक्षा का माहौल उम्दा है. नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग नक्शे के लिहाज से तीन हिस्सों में विभाजित है. दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिला आता है. मध्य बस्तर में बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, उत्तर बस्तर में कांकेर जिला आता है. 2018 के बाद, 7 सालों में यह पहला मौका है जब, सीएम ने दंतेवाड़ा तक की दूरी को सड़क मार्ग से तय किया है.

अमेरिका ने फिलिस्तीनी वीजा पर लगी पाबंदियों को बढ़ाया

वाशिंगटन 1 सितंबर. अमेरिका ने फिलिस्तीनी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा पाबंदियों को बढ़ाते हुए वीजा की लगभग सभी श्रेणियों के अनुमोदन पर रोक लगा दी है.

एक रिपोर्ट के अनुसार कहा कि लगाई गई वीजा पाबंदी में चिकित्सा, विश्वविद्यालय अध्ययन, व्यावसायिक यात्रा, और मित्रों या परिवार से मिलने की श्रेणी के आवेदन भी शामिल हैं. अमेरिकी विदेश विभाग के ये नियम केवल गाजा के निवासियों पर लागू होते थे पर अब नई नीति पश्चिमी तट और पूरे प्रवासी समुदाय में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों पर लागू हो जाएगी. इससे पहले इसी महीने के

शुरुआत में ट्रम्प प्रशासन ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सदस्यों के वीजा आवेदन रद्द कर दिए थे. जिससे उनके न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने से रोक लग गई थी. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया गया है और उसने फिलिस्तीनी नेताओं पर आतंकवाद छोड़ने में विफल रहने का आरोप लगाया.

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन चौथे दिन जारी

मुंबई, 1 सितंबर. मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सोमवार को चौथे दिन में प्रवेश कर गयी जबकि इस आंदोलन से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने मामले से निपटने के लिए ज्यादा समय की मांग की है. जरांगे ने घोषणा की थी कि वह सोमवार से पानी पीना बंद कर देंगे. उन्होंने अपनी मांग पर अडिग रहते हुए कहा कि मराठाओं को कुणबी के रूप में घोषित करने की मांग की है ताकि उन्हें आरक्षण के लाभ मिल सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार उन्हें यह दर्जा नहीं देती, वह अपना विरोध वापस नहीं लेंगे. महाराष्ट्र में कुणबी एक बड़ा और विविधतापूर्ण किसान समुदाय है.

इटावा में भाजपा-कांग्रेस समर्थकों के बीच पथराव, आठ हिरासत में

इटावा , 1 सितंबर. इटावा जिले के कैंट क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पथराव हुआ.

इस मामले में आठ कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया है. नगर पालिका चौराहे पर पुल हुयी पथराव की घटना के बारे में कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन सत्ता के इशारे पर कांग्रेसियों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने में जुटी हुई है जबकि सच्चाई इससे इतर है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत से भाजपाइयों पर पथराव किया जबकि भाजपा समर्थकों की ओर से नीचे से कांग्रेस जनों पर पथराव किया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इटावा के अपर जिलाधिकारी एसपी सिटी सीओ सिटी समय तमाम अधिकारियों को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना पड़ गया.

इंग्लैंड में एच5एन1 बर्ड फ्लू की पुष्टि

लंदन, 1 सितंबर. इंग्लैंड का दक्षिणी-पश्चिमी हिस्सा एच5एन1 बर्ड फ्लू रोग से पीड़ित है. ब्रिटिश सरकार ने बताया कि इंग्लैंड के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के गांव एक्समिंस्टर में एक पॉल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लूएंजा एच5एन1 के प्रकोप की पुष्टि हुई है. ब्रिटिश सरकार ने बताया कि घटनास्थल के चारों ओर 3 किलोमीटर का एक सुरक्षा क्षेत्र और 10 किलोमीटर का निगरानी क्षेत्र स्थापित किया गया है. परिसर में मौजूद सभी पॉल्ट्री फार्मों को मानवीय आधार पर खत्म कर दिया जाएगा.

घर-घर जाकर जुटाएंगे मदद : केजरीवाल

- बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्यकर्ता जुटाएंगे राहत सामग्री

नई दिल्ली, 1 सितंबर. पंजाब में बाढ़ की विकराल स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर राहत अभियान चलाने का निर्देश दिया है.

उन्होंने न केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ़ से सहायता देने की बात कही, बल्कि दिल्लीवासियों से भी अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में जितना संभव हो मदद करें. पंजाब में आई बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. ऐसे समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न केवल स्वयं राहत अभियान में योगदान देने की बात कही है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर राहत सामग्री जुटाने के निर्देश भी दिए हैं. यह अभियान दिल्ली से पंजाब तक मानवता की एक मजबूत कड़ी के रूप में देखा जा रहा है. मैं अपनी तरफ़ से अपनी क्षमता अनुसार योगदान कर रहा हूं.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस राहत अभियान के लिए एक केंद्रीय समन्वय टीम बनाई है जो पूरे राहत कार्य की निगरानी करेगी. साथ ही जरूरतमंद इलाकों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर सामग्री भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि देशवासियों के साथ खड़े होने का है। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस कार्य को सिर्फ एक अभियान न समझें, बल्कि इसे अपना नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व समझें. यह पहल एक बार फिर यह साबित करती है कि जब देश संकट में होता है, तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म बन जाती है. दिल्ली से पंजाब तक यह राहत यात्रा अब सिर्फ सामग्री नहीं, बल्कि संवेदनाओं की एक पुल बन चुकी है.

इलाहाबाद, केरल उच्च न्यायालयों के लिए चार न्यायाधीश नियुक्त

नई दिल्ली, 1 सितंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दो उच्च न्यायालयों के लिए चार न्यायाधीशों की नियुक्ति की है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को उनकी नियुक्ति से संबंधित ये घोषणा की. अधिवक्ता अरुण कुमार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इसी प्रकार केरल उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन, न्यायमूर्ति जी यू गिरीश और न्यायमूर्ति सी एन प्रतीप कुमार को पदोन्नत कर स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति किया.

भविष्य को आकार देने में जुटा एनसीईआरटी

- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी के 65वें स्थापना पर किया संबोधित

नई दिल्ली, 1 सितम्बर. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिष-एनसीईआरटी को भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अद्वितीय संस्थान बताते हुए कहा है कि उसने प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ छात्रों के भविष्य को आकार दिया है.

प्रधान ने सोमवार को यहां एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीईआरटी ज्ञान-कुंभ है जिसने अपनी स्थापना के बाद से शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अद्भुत

योगदान दिया है. उन्होंने एनसीईआरटी से सुधारोन्मुख, तकनीक-संचालित और वैश्विक सर्वोत्तम विधियां अपनाने का आग्रह किया. केंद्रीय मंत्री ने एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर सोमवार को यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई पहलों का शुभारंभ किया. इस मौके पर उन्होंने ओडिशा की 100 महान हस्तियों के जीवन और योगदान पर आधारित उत्कल जननींकर सुजोग्य संतान पुस्तक का भी विमोचन किया. प्रधान ने कहा कि 2047 तक समृद्ध भारत का निर्माण तभी संभव होगा.

केंद्रीय मंत्री ने एनसीईआरटी से अमृत शिक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और ज्ञान को योग्यता में बदलने की दिशा में काम करने के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने का आग्रह किया और विश्वास जताया कि यह संस्थान शैक्षिक सुधारों, शिक्षण और अधिगम में परिवर्तन के साथ समृद्ध भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

एक नजर में

पुतिन ने भारत के प्रयासों की सराहना की

तियांजिन, 1 सितंबर. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट में मध्यस्थता के लिए भारत और चीन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उनकी पहल ने चल रही शांति वार्ताओं को और मूल्यवान बनाया है. तियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में बोलते हुए श्री पुतिन ने यह बात कही. वह यूक्रेन संकट पर रूस का पक्ष रख रहे थे. इससे इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुतिन के साथ हुई बैठक में भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं. हाल ही में किये गये शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं. हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष रचनात्मकता के साथ आगे बढेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा, यह पूरी मानवता की पुकार है.

इंडोनेशिया राष्ट्रपति ने शांति का संकल्प दोहराया

जकार्ता, 1 सितंबर. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने देश भर के कई क्षेत्रों में हो रहे हालिया प्रदर्शनों के मद्देनजर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने का संकल्प दोहराया है. उन्होंने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि राजनीतिक दलों ने अपने उन सदस्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है जिन्होंने संसद में दुर्व्यवहार किया था. इसमें उनकी सदस्यता, भत्ते और विदेश यात्राएं रद्द करना शामिल है. उन्होंने प्रतिनिधि सभा के नेताओं से समुदाय के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के समूह के साथ बातचीत शुरू करने का भी आह्वान किया है. राष्ट्रपति ने कुछ क्षेत्रों में अशांति की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर प्रदर्शन अराजकता में बदलने लग जायें तो तो प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदार एजेंसियों को मूक नहीं बने रहना चाहिए. उन्होंने पुलिस और सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि वे कानून का पालन करते हुए दृढ़ता से काम करें और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये सरकारी संपत्ति की रक्षा करें. श्री प्रबोवो ने नागरिकों से शांति व्यवस्था बनाए रखने,किसी के उकसावे में नहीं आने और देश की एकता एंव स्थिरता बनाए रखने की अपील की है.

गोरखपुर में 700 करोड़ के निवेश से लगेगा प्लांट

गोरखपुर, 1 सितम्बर. बहुर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के बाद गोरखपुर में 700 करोड़ के निवेश से कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट लगाया जायेगा. गीडा के सेक्टर 27 में कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट की स्थापना के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास चार सितंबर (गुरुवार) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होना संभावित है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्लास्टिक पार्क में 120 करो? रुपये के निवेश से बनी तीन औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण, 640 करो? रुपये के निवेश वाली तीन यूनिट्स का शिलान्यास, औद्योगिक भूमि के आवंटन पत्र का वितरण, 400 करोड़ रुपये की लागत वाली कालेसर आवासीय योजना सेक्टर 11 के आवंटन पत्र का वितरण, सीईटीपी व सीपेट का शिलान्यास और 281 करोड़ रुपये के अवस्थापना विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाना भी प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री निजी क्षेत्र व गीडा की कुल मिलाकर 2251 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे.

बरसी पर धामी ने शहीदों को किया याद

खटीमा/नैनीताल, 1 सितंबर. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

उन्होंने इस मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों के

लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन जबकि घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6000 और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है. नए कानून के तहत चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. आंदोलनकारियों को पहचान पत्र जारी करने के साथ ही 93 आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में सेवायोजित भी किया गया है. यही नहीं आंदोलनकारियों को सरकारी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन में नारी शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है.

राज्य निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका को देखते हुए ही राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. उत्तराखंड ने देश में सबसे पहले 'समान नागरिक संहिता' को लागू किया है. देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके बाद लगभग 24 हजार से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है.

आज का इतिहास

1783 जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया।

1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।

1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।

1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।

1911 भारत के प्रसिद्ध बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म।

1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म।

1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।

1945 बंगलोर स्थित विप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी का जन्म।

राष्ट्रपति जेलेंस्की को शांति वार्ता को लेकर हत्या का है डर : जेफरी

वाशिंगटन 1 सितंबर. अमेरिकी अर्थशास्त्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय में सतत विकास केंद्र के निदेशक जेफरी सैक्स ने आशंका व्यक्त की है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, अपने देश के कट्टर राष्ट्रवादियों के डर से बातचीत के जरिए शांति समझौते के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं.

आरआईए नोवोस्ती को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने यह बात कही. यह साक्षात्कार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पहले आयोजित किया. यह सम्मेलन व्लादिवोस्तोक में तीन से छह सितंबर तक चलेगा. अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स संयुक्त राष्ट्र विकास एजेंडा 2030 से आगे सत्र में

अपनी बात रखेंगे. पिछले महीने हुए एक सर्वे के मुताबिक यूक्रेन की अधिकांश जनता चाहती है कि बातचीत के आधार पर यह जंग रुक जाए. श्री सैक्स ने कहा कि श्री ज़ेलेंस्की में ऐसा करने के क्षमता नहीं दिखती, चाहे यह उनकी व्यक्तिगत सीमा है या जैसा मुझे बताया गया कि वह डर रहे हैं कि अगर उन्होंने समझौता करने की कोशिश की तो कट्टर राष्ट्रवादियों के हाथों वह जान गंवा बैठेंगे.

नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के लिए चरणबद्ध समझौते को खारिज किया

तेल अवीव, 1 सितंबर. इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को एक बार फिर बंधकों की चरणबद्ध रिहाई से इनकार कर दिया और कहा कि आंशिक युद्धविराम और बंधक-रिहाई समझौता मेज पर नहीं है.

रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष विराम पर अपने रुख को दोहराया. उनका यह यह बयान युद्ध कैबिनेट के छह घंटे लंबे सत्र के बाद आया. इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कथित तौर पर किसी भी समझौते के लिए किसी भी आंशिक रूपरेखा को स्वीकार करने के खिलाफ आधिकारिक वोट के लिए दबाव डाला. नेतन्याहू ने कहा, वोट की कोई आवश्यकता नहीं है. यह मेज पर नहीं है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनका रुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से भी प्रभावित हो सकता है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को फोन किया था और उन्हें बताया था कि हमास के साथ किसी भी आंशिक समझौते को स्वीकार करने के बजाय इज़रायल को आतंकवादी समूह से पूरी ताकत से लड़ना चाहिए. ट्रम्प ने कहा आंशिक समझौतों को भूल जाइए. पूरी ताकत से आगे बढ़िए और इसे पूरा कीजिए. कहा जा रहा है कि श्री ट्रम्प श्री नेतन्याहू पर हमास को हराने के लिए गाजा में आईडीएफ की बढ़त को तेज करने का दबाव बना रहे हैं.

निर्देश | कारागार प्रशासन व सुधार सेवा की बैठक में सीएम योगी ने नीति पारदर्शी बनाने कहा

गंभीर बीमार बंदियों की रिहाई के नियम सरल हो

लखनऊ, 1 सितम्बर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित नियमों को और अधिक सरल, स्पष्ट तथा मानवीय दृष्टिकोण से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता जताई.

सोमवार को कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नीति को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पात्र

बंदियों की रिहाई स्वत: विचाराधीन होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से आवेदन न करना पड़े. उन्होने निर्देश दिए कि प्राणघातक रोग से पीड़ित होने की आशंका वाले सिद्धदोष बंदी, जिसे मुक्त करने पर उसके स्वस्थ होने की उपयुक्त संभावना है तथा वृद्धावस्था, अशक्तता या बीमारी के कारण भविष्य में ऐसा अपराध करने में स्थायी रूप से असमर्थ बंदी, जिसके लिये वह दोषी ठहराया गया हो के साथ-साथ घातक बीमारी या किसी प्रकार की अशक्तता से पीड़ित सिद्धदोष बंदी जिसकी मृत्यु निकट भविष्य में होने की संभावना हो, के संबंध में प्रदेश के सभी कारागारों में सर्वेक्षण कर वास्तविक संख्या का आकलन किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कैदियों को कृषि, गोसेवा आदि कार्यों से जोड़कर उनकी जेल अवधि के सदुपयोग करने के लिए व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल में यह भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक है कि किन बीमारियों को असाध्य रोग की श्रेणी में रखा जाएगा. उन्होने कहा कि समाज की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसलिए समयपूर्व रिहाई उन्हीं मामलों में की जानी चाहिए जहां से सामाजिक जोखिम न हो.